

## नवभारत

संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी

प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

मध्य क्षेत्र की डायरी

## मध्यप्रदेश में नशे से मौत के सौदागरों पर कसमें शिकंजा



दिलीप झा

पकड़ने का अपना काम कर रही है, लेकिन युवाओं को नशे की दल दल में धकेलने के पीछे कौन कौन सफेदपोश लोग हैं, उन्हें बेनकाब किया जाना बेहद जरूरी है. क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी अगर नशे की लत से जकड़ जाएगी तो उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है.

सूत्र बताते हैं कि भोपाल, जबलपुर और इंदौर नशे के सौदागरों का बड़ा अड्डा बन गया है. इन महानगरों में राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब से यहां गांजा, चरस, अफीम एवं एमडी ड्रग्स की सप्लाई होती है और फिर छोटे शहरों के युवाओं को नशे के दल दल में धकेल दिया जाता है. सरकार को यह भलीभांति समझना चाहिए कि युवा जब नशे में लिप्त होते हैं तो यही से आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं. गत दिनों भोपाल से एमडी ड्रग्स के साथ एक महिला को पुलिस ने पकड़ा है और बुधवार 19 नवंबर को हरदा जिले से पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने 490 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 98 लाख रुपए बताई जा रही है. लोग सरकार से सबसे अहम सवाल यह कर रहे हैं कि आखिर एमडी ड्रग्स की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगेगा क्योंकि समाज पर इसका बहुत बुरा असर पर रहा है. नशे की चपेट

में आने से घर परिवार बिखर रहा है. पिछले साल भी राजधानी भोपाल से भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स पकड़े गए थे. लेकिन उस मामले में भी बहुत बड़ा खुलासा नहीं किया गया.

## मोहन सरकार को क्या करना चाहिए

मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड से काम करने की छूट देनी चाहिए. पुलिस पर राजनीति जब हावी होने लगती है पुलिस की प्रशासनिक गाड़ी ड्रिबल हो जाती है. इसके पीछे का लॉजिक भी हमें समझना होगा कि जब राजनैतिक हलकों से किसी अपराधी को छुड़ाने के थाना पुलिस पर दबाव बनता है तो पुलिस का मनोबल गिरता है. पुलिस को अपरिहार्य कार्यों से जब अपराधियों को छोड़ना पड़े तो जाहिर है उनमें नाराजगी होती है.

अपराधियों को पकड़ने अथवा अपराध के तह में जाने के लिए पुलिस प्रशासन को गहन पड़ताल करनी होती है और तमाम कठिनाइयों के पापड़ बेलने पड़ते हैं. ऐसे में जब राजनैतिक गलियारों से थाने में फोन आता है कि उक्त अपराधी को छोड़ दें तो सोचिए कि क्या किसी पुलिस अधिकारी पर क्या गुजरता होगा. यह ध्रुव सत्य है पुलिस के मनोबल को बढ़ाए बिना आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण कतई संभव नहीं है. राजनीतियों को इस पर गहनता से विचार करना होगा कि पुलिस के कार्यक्षेत्र में वो दखल नहीं दे. कुछ राजनेता अर्थात माननीय अपने वोट बैंक के कारण अपराधियों को बचाने के लिए उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हो जाते हैं और इसका बड़ा खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है. सूत्रों का कहना है कि विधायकों का थाने में हस्तक्षेप बढ़ने के कारण टीआई भी अपने मन से पुलिसिंग नहीं कर पाते हैं.

## दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर एमपी पुलिस

दिल्ली ब्लास्ट के तार मध्यप्रदेश से जुड़ने के बाद यहां की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है. अलकल्लाह यूनिवर्सिटी के संचालक जवाब अहमद सिद्दीकी मूल रूप से इंदौर के महु का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि उसने 25 पहले एक निवेश कंपनी खोलकर हजारों लोगों का करोड़ों रुपये का चूना लगाया है. वह पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए महु से भागकर फरीदाबाद में आतंक की फैक्ट्री खोलकर बैठ गया. इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्सिटी चलाने की अनुमति किसने और क्यों दी? सबसे हेरानगी की बात है कि अभी तक वह पुलिस की गिरफ्तार में क्यों नहीं आया. ? किसकी मेहरबानी इस पर थी, किसके शह पर देश विरोधी गतिविधियों में वह लिप्त था जैसे तमाम सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस दोनों को चाहिए. हालांकि इस मामले में नित नत खुलासे उतर प्रदेश और हरियाणा से भी हो रहे हैं. एनआईए ने तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है. आतंकियों ने 32 कारों में विस्फोटक लेकर पूरे देश में विस्फोट करने का प्लान रचा था. लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में बड़ी मुस्तेदी के साथ आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और हजारों लोगों की जान बच गई.

## राज्यपालों की भूमिका व संवैधानिक मर्यादा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ताजा फैसला लोकतंत्र की मर्यादा और शासन व्यवस्था की साख को मजबूत करने वाला है. लंबे समय से कई राज्यों में निर्वाचित सरकारों और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बनी रही, जहां राज्यपालों द्वारा विधेयकों को महीनों तक लंबित रखा गया. अदालत ने इस प्रवृत्ति पर सख्त नाराजगी जताते हुए साफ कर दिया है कि राज्यपाल के पास विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोककर रखने का कोई अधिकार नहीं है. अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए शीर्ष अदालत ने तीन विकल्पों को ही संवैधानिक माना है. विधेयक को मंजूरी देना, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना. अदालत ने कहा कि इन तीन रास्तों के अलावा किसी विधेयक को 'ठंडे बस्ते' में अलकन निष्क्रियता दिखाना संविधान की भावना के विरुद्ध है. यह स्पष्ट रेखांकन उन राज्यों के लिए खास तौर

पर महत्वपूर्ण है, जहां राजनीतिक मतभेदों के कारण राजभवन विधेयक प्रक्रिया के बीच बाधा बनता गया. इस फैसले का पहला बड़ा संदेश है, जवाबदेही. राज्यपाल कोई राजनीतिक पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि एक संवैधानिक प्रहरी हैं. जनता द्वारा चुनी गई सरकार के कामकाज को अटकाना न तो नैतिक है और न ही संवैधानिक. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर निर्णायक रोक लगा दी है, जो लोकतंत्र की बड़ी जीत है.

दूसरा, अदालत ने सहयोगी संघवाद की अनिवार्यता पर जोर दिया है. राज्यों की विधानसभाएं जनता की अदालत से सीधे जुड़ी होती हैं. यदि राज्यपाल ही विधायी प्रक्रिया को रोकते रहें, तो पूरा तंत्र अविश्वास और खींचतान का अखाड़ा बन जाता है. न्यायालय का यह फैसला राजभवन को यह याद दिलाता

है कि वह केंद्र की नीति का विस्तार भर नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक संस्था है, जिसका कर्तव्य निर्वाचित सरकार के साथ समन्वय बनाकर चलना है. तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भले कोई सख्त समय सीमा न तय की हो, लेकिन यह जरूर कहा है कि यदि राज्यपाल को किसी विधेयक पर आपत्ति है, तो उसे 'जितनी जल्दी हो सके' वापस भेजा जाए. यह टिप्पणी उन अनावश्यक देरी और प्रशासनिक उदासीनता पर सीधा प्रहार है, जिनके कारण कई बार शासन व्यवस्था टप पड़ जाती है. यह फैसला राज्यपालों के लिए एक स्पष्ट नसीहत भी है. यह याद रखने की प्रवृत्ति रखें. निश्चित ही, यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करेगा और केंद्र-राज्य संबंधों में जरूरी सामंजस्य की राह खोलेगा. यह न केवल संवैधानिक मर्यादाओं को पुनर्सथापित करता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है और उसे रोकने की कोई गुंजाइश अब शेष नहीं है.

पालन करें, जनता के जनादेश का सम्मान करें और संविधान की मर्यादा में रहते हुए कार्य करें. 'स्पीड पोस्ट' की तरह समयबद्ध प्रक्रिया अपनाता ही राजभवन की मर्यादा और जनता के विश्वास दोनों की रक्षा करेगा.

राजभवन और सचिवालय के बीच संवाद की कमी से पैदा होने वाले टकराव अब समाप्त होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारतीय संविधान किसी पदाधिकारी को असीमित अधिकार नहीं देता. अब राज्यपालों पर जिम्मेदारी है कि वे इस फैसले की आत्मा को समझें और संवैधानिक गरिमा का पालन सुनिश्चित करें. निश्चित ही, यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करेगा और केंद्र-राज्य संबंधों में जरूरी सामंजस्य की राह खोलेगा. यह न केवल संवैधानिक मर्यादाओं को पुनर्सथापित करता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है और उसे रोकने की कोई गुंजाइश अब शेष नहीं है.

## जुगाड़ बार-बार, नीतीश बने सीएम 10वीं बार

नीतीश के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का कारण सिर्फ उनकी लोकप्रियता भर नहीं है, इसमें उनके फॉर्मूला भारत होने का भी योगदान है. वर्तमान में भारत की चुनावी राजनीति का फॉर्मूला लगता है, अब एक नए संक्रमणकाल से गुजर रहा है. भारतीय लोकतंत्र की चुनावी यात्रा के अब तक के सफर में नए प्रचलन स्थापित हो रहे हैं. पहले पिछड़ी दलित अगड़ी और अल्पसंख्यक मुस्लिम के आधार पर पार्टियां मतदाताओं का समीकरण तैयार करती थीं, अब वह वर्गीकरण दरकना शुरू हो चुका है. अब मुख्य रूप से तीन राजनीतिक वर्ग रेखांकित हो रहे हैं, ये हैं किसान, युवा और महिला. इसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक वर्ग महिला का बना है. किसान और युवा पहले ही राजनीतिक दलों का इमोशनल डोमेन हुआ करता था पर अब महिला मतदाता का जेंडर समूह एक बड़ा पॉलिटिकल डोमेन बनकर उभरा है, क्योंकि संख्या के हिसाब से यह आधी आबादी है. महिलाओं के लिए प्राधानित मासिक या एकमुश्त भता दिए जाने की जो होड़ लगी है चाहे उन्हें आजीविका के साधन के नाम पर दिया जाए, चाहे युवा महिला वर्ग को पढ़ाई और छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाए या फिर लड़कों की शादी के लिए दिया जाए.

गौरतलब है कि महिलाओं के लिए धन स्थानांतरण के इस राजनीतिक आइडिया



## महिलाओं का मिला भारी समर्थन

चुनावी पंडितों की तमाम नकारात्मक भविष्यवाणियों के बावजूद आखिरकार नीतीश कुमार बिहार के 10 वीं बार मुख्यमंत्री बन गए. इसी के साथ ही उन्होंने संख्या के हिसाब से देश में किसी भी राज्य के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बना दिया, लेकिन ज्यादा समय तक, दिनों के हिसाब से मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग का है. वह 24 साल 165 दिनों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं.

कोई जगह योजना का रूप दिया गया. जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, कहीं धनलक्ष्मी योजना, तो कहीं महिला आजीविका योजना के रूप में ये दृष्टिगोचर हुआ. इस क्रम में हरियाणा की सैनी सरकार, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले महिलाओं के आर्थिक हितों की इन घोषणाओं को योजनाओं में अंजाम दिया. इसका परिणाम ये हुआ कि इन तीनों प्रदेशों में पदास्वकार सरकारें पुनः विजयी हो गईं. यही प्रयोग बिहार की पदास्वकार सरकार ने भी प्रदेश की 75 लाख महिलाओं को दस हजार की एकमुश्त आजीविका कमाई की राशि के रूप में स्थानांतरित कर किया है.

हर राज्य में चुनावी रेवडी- कुल मिलाकर मुफ्त और रेवडी भारतीय लोकतंत्र की चुनावी राजनीति का सबसे

बड़ा फॉर्मूला बनकर उभरा है. बताया जाता है कि बिहार सरकार को महिला आजीविका के एवज में कुल 40000 करोड़ की राशि स्थानांतरित करनी पड़ी है. इससे पूर्व रेवडी की राजनीति शुरू करने के एवज में कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई. इसी तरह महाराष्ट्र में भी लाडकी बहोण योजना से खजाने पर भारी बोझ पड़ा है. प्रश्न ये है इस बोझ से कैसे निपटा जाएगा? देश के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनके घरेलू राजस्व कमाई की हिस्सेदारी उनके कुल बजट में दो तिहाई से ज्यादा है जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं पर बिहार शराबबंदी की वजह से पहले से ही करीब 5 से 10 हजार करोड़ सालाना राजस्व का नुकसान उठा रहा है. उसे मुफ्तखोरी की मार ज्यादा झेलनी पड़ेगी

बशर्ते डबल इंजन की सरकार से उसे अतिरिक्त वित्तीय ताकत प्राप्त हो. चुनाव में लोकलुभावनावाद और रेवडी संस्कृति पर भी दो वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की एक लक्ष्मण रेखा तय किए जाने की पुर्जोर वकालत की गई. पर प्रतियोगी चुनावी व्यवस्था में कोई भी दल इस पर अभी तक उसी तरह से हामी नहीं भर पाए, यदि बिहार की बात करें तो सत्तारूढ़ दल ने अपनी घोषणा पर 40 हजार करोड़ खर्चें. हालांकि बिहार का चुनावी परिणाम केवल रेवडी का खेल था, ऐसा नहीं कहा जा सकता बल्कि नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए का भरोसा भी लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा था, जिस तथ्य को सभी राजनीतिक पंडितों को स्वीकार करना पड़ा.

-मनोहर मनोज

## आतंकी मामलों का शीघ्र निपटारा आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह एनआईए मामलों को जल्दी निपटारने में सहयोग दे. इसके लिए सरकार को 6 माह की मुहत्त दी गई है. देश में न्याय की गति धीमी है जिसकी एक वजह जजों की कमी मानी जाती है. जुलाई में देश के उच्च न्यायालयों में जजों के 371 पद खाली थे. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखने के लिए 50 स्वीकृत एनआईए अदालतों में से 3 ने केवल एनआईए मामलों पर गौर किया. इसका अर्थ यह है कि इन अदालतों के जज सामान्य आपराधिक मामलों और बड़े आतंकी मामलों के बीच अपना समय बांट लेते हैं. दूसरी ओर हजारों विचारधीन कैदी जेल में रहने को बाध्य है जिनकी जमानत हो सकती है. इनमें गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग और बुजुर्ग शामिल हैं. आतंकवाद को वित्त पोषण (फंडिंग) के मामले में बारमूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख लंबे समय से जेल में कैद हैं. उन्हें संसद सत्र में भंग लेने के लिए हर बार पैरोल लेना पड़ता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में चेतावनी दी थी कि यदि एनआईए के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में बहुत अधिक विलंब हुआ तो वह विचारधीन कैदियों को रिहा कर देगा. तब से सरकार एनआईए अदालतों को मजबूत करने की दिशा में प्रयत्नशील है.



यथाशीघ्र सजा मिल सके.

देश के 11 राज्यों से संसद में बात चल रही है लेकिन 10-12 विशेष एनआईए अदालतों की स्थापना के लिए जगह की समस्या सामने आ रही है. इतना ही नहीं, एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के पास स्ट्राफ की भी समस्या है जिसकी वजह से जांच धीमी पड़ जाती है. इसमें 1,901 पद स्वीकृत हैं जिनमें से जून माह में 541 या 28 प्रतिशत पद खाली पड़े थे. इनमें कोस्टगार्ड से लेकर इस्पेक्टर तक के पदों का समावेश है. गत 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के निकट हुए विस्फोट के बाद इन पदों पर भर्ती को प्राथमिकता देनी होगी ताकि आतंक के गुनहगारों को यथाशीघ्र सजा मिल सके. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस दिशा में 16 दिसंबर तक पक्का निर्णय लेने को कहा है.

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

**CROSS WORD 12088** - डॉ. सागर खादीवाला

1	2	3	4	5
6				
	7		8	
9		10		11 12
		13		14
15 16				
17	18		19	
20				

(सं.) 3 गरम, तपाया हुआ, कूड़ (सं.) 5. किसी भारी वस्तु से जोर से दबाना, पैरों से रौंदना 7. लाचार, विवश, असहाय (उर्दू) 8. बिल्कुल ठीक, व्याख्या सहित 10. चुभाना, गाड़ना, ठेलना 12. किसी वस्तु की आकृति रंग-गुण दोष आदि से, परिचित होना, किसी पूर्व परिचित व्यक्ति या वस्तु को देखकर यह जान लेना कि वह अमुक है 14. किसी काम में या किसी निर्वाचन में होने के लिए किसी का नाम लिखा जाना 15. वर्ष, साल 16. समूह, समुदाय 18. नली, अर्धचंद्राकार लोहे का टुकड़ा जो जुते या घोड़े की टाप में लगाया जाता है 19. आमदनी

**Solution 12087**

मे	घ	ना	रू	उ	त	ना
रू	र	रू	रू	त	रू	प
ला	सा	र	र	सि	क	
म	घ	ख	ना	स		
जा	मु	न	ना	च	ना	
रा	घ	या	ल	सा		
पा	व	रो	टी	न	से	नी

**बाएँ से दाएँ**  
1. हस्ताक्षर किया हुआ, जिसमें हस्ताक्षर किए हुए हों (सं.) 4. दुर्बोधन का मामा (महाभारत) 6. उम्र, अवस्था (सं.) 8. सहज, सुगम, निष्क्रप 9. इंद्रवधु, गहरे लाल रंग का एक बरसाती कीड़ा 11. परिमाण, माप 13. खिसकना 15. पर्याप्त, भरपूर, उहरो 17. लीन या अनुसृत करना 19. गिनना, अनुसंधान, खाने में जमा करना (सं.) 20. जिसकी आंखें अश्रुपूर्ण हो

**ऊपर से नीचे**  
1. जो अपने भरोसे या सहारे पर रहता हो 2. ह्रस, नाश, यक्ष्मा रोग

## ज्योतिषाचार्य प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

## आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ का योग है, वर्ष के मध्य में व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, शासन सत्ता का सुख प्राप्त होगा, वर्ष के अन्त में शारीरिक कष्ट होगा, मित्रों से व्यर्थ विवाद होगा, स्थानान्तरण का योग है, मानसिक तनाव में वृद्धि होगी.

मेघ और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट होगा, वृष

**मेघ**- लाभकारी योजना बनेगी, भवनात्मक संबंधों में मधुरता आएगी, विशेष श्रम एवं प्रयास करने का योग है, मनः स्थिति संतोषप्रद रहेगी.

**वृषभ**- मेहनतानों की आवाजाही से घर में उल्लास का माहौल रहेगा, नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, शीघ्र कार्य शुभारंभ होगा, मित्रता उपयोगी रहेगी.

**मिथुन**- समय पर कार्य न होने से परेशानी होगी, नैकरी संबंधी प्रयासों में सफलता मिलेगी, राजकीय सहयोग मिलेगा, सुविधाओं को वृद्धि होगी.

**कर्क**- विरोधी की चालों से सावधान रहें, राजकीय मामले आपसी बातचीत से सुलझ सकते हैं, धार्मिक संस्कार से मानसिक शांति रहेगी, निर्णयता से कार्य करें.

**सिंह**- आय के नये स्रोत बनेंगे, शारीरिक शिथिलता बनेगी, पुन्य व्यक्तियों की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी, विवादों को टालने का प्रयास करें.

**कन्या**- सहाय्यता के हिसाब से कार्य योजना में परिवर्तन कर लेंगे, अधिकारी सहमत होंगे, व्यवसायिक कार्यों को अधिकता रहेगी.

**तुला**- अनुभवी लोगों की सलाह से दुविधा दूर होगी, खानपान पर ध्यान रखें, आर्थिक लेनदेन में सावधानी, कार्य को अधिकता रहेगी.

**वृश्चिक**- अनहोनी का भय रहेगा, सामाजिक कार्य में आपकी उपस्थिति प्रसन्नता देगी, संतान के कारण भावनात्मक पीड़ा हो सकती है, खानपान पर संयम रखें.

**धनु**- कार्यस्थल पर सुधार के लिये दिन-रात एक कर देंगे, दायमत्व खत्म मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मित्रों का समागम होगा.

**मकर**- जरूरी कार्य के लिये किसी का सहयोग लेना पड़ेगा, मित्र के रूखे व्यवहार से खिन्नताहोगी, शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ेगा, लाभ में कमी आयेगी.

**कुम्भ**- कार्य की गति धीमी होने से परेशानी होगी, लेनदेन को चिन्ता रहेगी, आकस्मिक खर्च होने का योग है, मित्रों परुषार्थ बना रहेगा.

**मीन**- स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पायेंगे, समय पर सोचे हुये कामकाज बचने का योग है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विद्याओं वर्ग को परिश्रम होगा.

## आज जन्म शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक हंसमुख, मिलनसार होगा, जन्म स्थान सू दूर रहकर अपनी उन्नति करेगा, अपनी मनमर्जी का मालिक होगा, आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, विशेष विद्या का ज्ञाता होगा.

**उदयकालीन ग्रह चाल**

**पंचांग**

रा.मि. 01 संवत् 2082 मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया शनिवासरं दिन 3/12, ज्येष्ठ नक्षत्रे दिन 3/52, सुकर्मा योगे दिन 11/33, कौलव करणे सू.उ. 6/40, सू.अ. 5/20, चन्द्र चार वृश्चिक दिन 3/52 से धनु, शु.रा. 8, 10, 11, 2, 3, 6 अ.रा. 9, 12, 1, 4, 5, 7 शुभांक-0, 3, 7.

## उदयकालीन ग्रह चाल

रा.मि. 01 संवत् 2082 मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया शनिवासरं दिन 3/12, ज्येष्ठ नक्षत्रे दिन 3/52, सुकर्मा योगे दिन 11/33, कौलव करणे सू.उ. 6/40, सू.अ. 5/20, चन्द्र चार वृश्चिक दिन 3/52 से धनु, शु.रा. 8, 10, 11, 2, 3, 6 अ.रा. 9, 12, 1, 4, 5, 7 शुभांक-0, 3, 7.

**व्यापार भविष्य**

मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया को ज्येष्ठ नक्षत्र के प्रभाव से रूई, कपास, सूत, के भाव में तेजी होगी, गेहूँ, जौ, चना, गुड़, खांड मूंग, मोठ, अरहर के भाव में तेजी होगी, भाग्यांक 2623 है.

**SUDOKU 7220**

9		6						
4	7		8	3				9
	8	7	3		1	2		
	8	9		5	1		7	6
5	1		8	7		4	9	
	2	4		6	5	7		
7		1	3				5	8
				1				4

रा.मि. 01 संवत् 2082 मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया शनिवासरं दिन 3/12, ज्येष्ठ नक्षत्रे दिन 3/52, सुकर्मा योगे दिन 11/33, कौलव करणे सू.उ. 6/40, सू.अ. 5/20, चन्द्र चार वृश्चिक दिन 3/52 से धनु, शु.रा. 8, 10, 11, 2, 3, 6 अ.रा. 9, 12, 1, 4, 5, 7 शुभांक-0, 3, 7.

प्रा.मि. 01 संवत् 7219

1	9	3	7	5	4	2	6	8
8	4	2	1	6	3	9	7	5
5	7	6	8	2	9	3	1	4
4	1	5	6	3	2	8	9	7
7	2	9	4	8	1	6	5	3
3	6	8	5	9	7	1	4	2
2	5	1	9	4	8	7	3	6
9	8	4	3	7	6	5	2	1
6	3	7	2	1	5	4	8	9

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. पहली का केवल एक ही हल है.